आकाशवाणी शिमला
30.07.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

प्रधानमंत्री बजट सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद–जीडीपी आठ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं जब यह वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज नई दिल्ली में ''विकसित भारत की ओर यात्रा'' नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय को संसाधन निवेश का सबसे बड़ा उत्पादक माध्यम कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2004 में यूपीए सरकार के पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90 हजार करोड़ रुपये था और 2014 में यह बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि बजट का आकार अब तीन गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मंत्रालयों के आवंटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है।

वन महोत्सव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बान का पौधा लगाकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस बार वन विभाग ने प्रदेश में जन भागीदारी से 9 हज़ार हैक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। इसके तहत वन रक्षक स्तर पर दो पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और पौधों की देखभाल के लिए सरकार ने फॉरेस्ट बीट के चौथे हिस्से को महिला मंडलों को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के पहले चरण की स्वीकृति के बाद परियोजना क्षेत्र में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की। इस दौरान राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों व 41 वन मंडलों में स्थानीय विधायकों, वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया और पौधरोपण अभियान से जुड़े। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30 हजार पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20 हजार नौकरियां सृजित की गई, जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव–पेच में फंस गई।

चंद्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटने के लिए पौधरोपण करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 75वें वन महोत्सव के दौरान जामुन का पौधा रोपित कर पौधरोपण के शुभारंभ अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने और आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर का पैसा रोक दिया जिससे अस्पतालों ने ईलाज करना बंद कर दिया और लोग दर–दर भटकने को मजबूर हुए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मित्रों को केबिनेट रेंक बांटने और सीपीएस बनाने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन गरीब हित और प्रदेश के विकास की बात आते ही सरकार को हर तरह की आर्थिक तंगी याद आती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुक्खू सरकार महिलाओं को बस किराए में मिल रही छूट की योजना और निशुल्क पानी जैसी योजनाओं को भी बंद करने की तैयारी कर रही है।

एबीवीपी

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की एक सौ 12 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने संबंधी सरकार के निर्णय के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शिमला में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर इस निर्णय को जल्द वापिस लेने की मांग की। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि पर्यटन गांव के लिए कृषि विश्वविद्यालय से भूमि लेने का निर्णय गलत है। इस दौरान एबीवीपी ने टैट की परीक्षा फीस को दुगना करने के निर्णय का भी विरोध जताया।

———————————————————————————————